

खाद्य प्रसंस्करण से कृषकों की आय में बढ़ोतरी होगी?

संदर्भ

पछिले महीने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के एक किसान प्रेम सहि चव्हाण ने थोक मूल्यों में आई गरिवट के बाद टमाटर और फूलगोभी की अपनी पूरी तरह से तैयार फसल को खेत में ही नष्ट कर दिया। इन फसलों के थोक मूल्यों में आई गरिवट के बाद फसल का इतना भी मूल्य प्राप्त नहीं होता कि उन्हें निकटतम बाज़ार में लाने व ले-जाने की लागत तक हासिल हो सके। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक स्तर पर देखा और साझा किया गया। वीडियो में नाराज़ और असहाय चव्हाण फूलगोभी को फेंकते और टमाटर के पौधों को उखाड़ते दिखाई दे रहा है।

- समाचार पत्र मटि द्वारा किसान प्रेम सहि से हुई बातचीत में यही बात सामने आई कि खेती के भरोसे जीवन यापन करना और अपने पूरे परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाना अब आसान काम नहीं रह गया है। ऐसी स्थिति में यदि प्रेम सहि जैसे किसान अपनी फसलों को मंडी में न्यूनतम लागत पर बेचने की बजाय किसी कांटेरेक्टर (फूड प्रोसेसिंग संबंधी) को बेचते हैं तो यह उनके लिये अधिक फायदेमंद एवं संतोषजनक होगा।

पूरे देश के किसानों की यही हालत है

- यह कहानी केवल प्रेम सहि की नहीं है बल्कि यह देश के लाखों किसानों की है। पछिले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि भले ही वो चाहे कर्नाटक में टमाटर के किसान हों या उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक अथवा मध्य प्रदेश के प्याज उत्पादक सभी की यही कहानी है।
- उचित मूल्य के अभाव में ये अन्नदाता अपनी मेहनत से सींची फसल को सड़क के किनारे फेंक रहा है। अक्सर देखने को मिलता है कि फसलों को खेतों में ही छोड़ दिया जाता है या फिर उनमें आग लगा दी जाती है, नहीं तो उन्हें वरिध स्वरूप सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है।
- कृषि उत्पादन में बढ़ती बागवानी फसलों की हसिसेदारी का ही परिणाम है जो वर्ष 2017-18 में देश में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस समयावधि में 30 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया। स्पष्ट है कि देश का पेट भरने वाले अन्नदाता को फसलों के आवरती मूल्य में आने वाले उत्तर-चढ़ाव से सुरक्षित रखा जाना चाहिये।
- इस स्थिति में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र एक अहम भूमिका का निर्वहण करता है। यह क्षेत्र मूल्य वृद्धि के माध्यम से किसानों को उनके परिश्रम की बेहतर कीमतें प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान समय में भारतीय कृषि उत्पादन का लगभग दसवां हिस्सा संसाधित हो रहा है और मंत्रालय का उद्देश्य इसे वर्तमान स्तर से तीन गुना बढ़ाने का है।

खाद्य प्रसंस्करण क्या है?

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का तात्पर्य ऐसी गतिविधियों से है जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है। उदाहरण के लिये डेयरी उत्पाद, दूध, फल तथा सब्जियों का प्रसंस्करण, पैकेट बंद भोजन तथा पेय पदार्थ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत आते हैं।

खाद्य प्रसंस्करण का महत्त्व

- दूध, मांस, समुद्री खाद्य पदार्थों में से हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त कर, उनमें अन्य पोषक तत्त्व मिलाकर खाने योग्य बनाने के लिये।
- खाद्य पदार्थों की उत्तरजीवित को बढ़ाने के लिये।
- किसानों का अतिरिक्त लाभ सुनिश्चित करने के लिये।
- नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ावा देने के लिये।
- रोजगार के नए अवसर सृजित करने हेतु।
- पोषण स्तर में सुधार करना।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- कृषि में विविधता को बढ़ावा देना।
- निर्यात आय को बढ़ावा देना।

भारत की स्थिति

- भारत बहुत बड़ी मात्रा में वदिशों से खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद आयात करता है। वर्तमान में देश में लगभग 370 अरब डॉलर मूल्य के खाद्य पदार्थों की

खपत होती है। वर्ष 2025 तक यह आँकड़ा 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर पहुँच जाने की संभावना है।

- यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापक स्तर पर कारोबारी नविश की संभावनाएँ हैं। भारत की संपूर्ण खाद्य मूल्य श्रृंखला में व्यापक अवसर उपलब्ध हैं, जिनमें फसल कटाई के उपरांत सुवर्धिएँ, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज चेन श्रृंखला और वनरिमाण शामिल हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का वसितार कथि जाए तो इसमें रोजगार की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। महिलाओं के लयि भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं, वशिषक देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करके महिलाओं के लयि सूक्ष्म-उद्यमयिों के रूप में उभरने की व्यापक संभावनाएँ हैं।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग वभिन्न आवश्यक सूचनाओं के जरयि कसिनों की मदद कर सकता है और खेती करने के बेहतर तरीके भी बता सकता है, ताकि उद्योगों को उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल सुलभ हों और कसिनों को उनकी उपज का वाजबि मूल्य मलि सके।

राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति

- इस नीति के अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय खाद्य ग्रिड (India's NATIONAL FOOD GRID) और राष्ट्रीय शीत श्रृंखला ग्रिड (NATIONAL COLD CHAIN GRID) के नरिमाण पर ध्यान केंद्रति कथि जाएगा तथा इसके साथ-साथ देश भर में कोने-कोने में खुदरा बाजार तैयार कथि जाएंगे।

इसके लाभ क्या-क्या होंगे?

- इस योजना के करयान्वयन से राज्यों/केंद्र-शासति प्रदेशों को राज्यों और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वकिस की कृषि योजनाओं के बीच सामंजस्य स्थापति करने में मदद मलिंगी। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी जससे कसिनों की आय में भी बढ़ोततरी होगी।
- बुनयिादी ढाँचे/संस्थागत अंतर को दूर करने के जरयि इससे कुशल आपूर्ति श्रृंखला सुनश्चिति करने में भी मदद मलिंगी।

गठन

- कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रि की अध्यक्षता में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण वकिस परिषद का गठन कथि गया है जसमें राज्य सरकारों, उद्योग संघ तथा भारत सरकार के संबंधति वभिण शामिल हैं। यह परिषद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एनएमएफपी सहति सभी योजनाओं को दशिा-नरिदेश प्रदान करेगी।

उद्देश्य

- एनएमएफपी का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय की योजनाओं के करयान्वयन को वकिेंद्रीकृत करना है जससे राज्य सरकारों तथा केंद्र-शासति प्रदेश की भी इसमें भागीदारी हो सकेगी।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के लाभार्थयिों को भी राज्य सरकारों के साथ संबंध बनाने में आसानी होगी।

शीत श्रृंखला और प्रसंस्करण इकाइयों की वास्तवकि स्थिति

- शीत श्रृंखला और प्रसंस्करण इकाइयों में बुनयिादी ढाँचे के अंतराल से कृषि उपज का एक बड़ा हसिा बरबाद भी होता है।
- लुधयिाना के सेंटरल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनयिरिंग एंड टेक्नोलॉजी (Central Institute of Post-Harvest Engineering and Technology) द्वारा 2015 के एक अध्ययन में यह जानकारी प्रदत्त की गई कि भारत में फलों और सबजयिों के संदर्भ में पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान तकरीबन 31,500 करोड़ रुपए रहा।
- इस अध्ययन के अनुसार, उपभोक्ता तक पहुँचने से पहले लगभग 7 से 12% सबजी उत्पादन बरबाद हो गया।
- कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतराल के आकलन के लयि एनसीसीडी (National Centre for Cold Chain Development - NCCD) द्वारा 2015 में शुरू कथि गए एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में फल और सबजयिों के भंडारण के लयि 32 मिलियन टन की स्टोरेज क्षमता नरिमति की गई है, जो 35 मीटर की आवश्यक क्षमता के करीब है, तथापि इस उपज के उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में काफी अंतराल आता है।
- अध्ययन से पता चला है कि उत्पाद को उपभोक्ताओं तक पहुँचाए जाने से पहले कसिनों को अपने खेतों के समीप तकरीबन 70,000 पैक हाउस (Pack houses) और 9,000 से अधिक रिपनिगि चैम्बरस (Ripening chambers) की आवश्यकता है। हालाँकि, वास्तवकि रूप में केवल 249 पैक हाउस और 812 रिपनिगि चैम्बरस ही मौजूद हैं।
- रिपोर्ट में पाया गया कि ऐसी उपज के लयि जो जल्द ही नष्ट हो जाती है (जैसे - फल और सबजी) के परिवहन के लयि लगभग 62,000 रेफर या रेफ्रिरेटेड वाहनों की आवश्यकता है, जबकि वास्तवकि रूप में केवल 9,000 वाहन ही उपलब्ध हैं।
- इस समस्या का समाधान करने के लयि 2017 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्रि कसिन संपदा योजना को 6,000 करोड़ रुपए के वत्तितीय परवियय (चार साल के लयि) के साथ लॉन्च कथि था।

प्रधानमंत्रि कसिन संपदा योजना

2016 से 2020 की अवधि के लयि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना 'संपदा' (SAMPADA) स्कीम फॉर एगरो-मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एगरो प्रोसेसिंग क्लस्टरस के अंतर्गत अन्य योजनाओं को पुनर्रसंचति करने का प्रयास कथि गया है। वशिषताएँ-

- इस योजना का उद्देश्य कृषि को पूरक बनाना, संसाधनों का आधुनकिकरण और कृषि उत्पादों के नुकसान को कम करना है।
- यह खाद्य संसाधन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के लयि एक 'अंबरेला स्कीम' है।
- मेगा फूड पार्क योजना का उद्देश्य देश में कृषि प्रसंस्करण इकाइयों हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना, डेयरी, मत्स्यन आदि कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्द्धन सुनश्चिति करना है।

- इसमें शामिल शीत शरुंखला और मूल्य संवर्द्धन योजना, पररिक्षण एवं आधारभूत संरचना सुवधियों की स्थापना में वित्तीय सहायता के माध्यम से बागवानी एवं गैर-बागवानी कृषि उत्पाद की कटाई उपरांत हानि को रोकना है।
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मुताबिक, इस योजना का उद्देश्य 31,400 करोड़ रुपए से अधिक नविश अर्जति करना, लगभग एक ट्रिलियन रुपए से अधिक के धन से कृषि उपज को समर्थन प्रदान करना, करीबन 20 मिलियन किसानों को बेहतर कीमतें उपलब्ध कराना तथा 2019-20 तक आधे मिलियन से अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन करना है।
- हालाँकि, कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के सांस्कृतिक क्रियाकलापों और भू-जलवायवीय स्थितियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि इस देश का उपभोक्ता कब क्या खा सकता है (अर्थात् प्रत्येक मौसम के हिसाब से यहाँ भोजन की आदतें बदलती रहती हैं), जो कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि को सीमित करने का काम करती हैं।
- भारत में, पश्चिमी देशों के विपरीत 99% ताज़ा कृषि उत्पादों का उपभोग किया जाता है। इसलिये भारत में प्रसंस्करण उद्योग वैसी स्थिति हासिल नहीं कर सकता है जैसी कि पश्चिमी देशों में है। पश्चिमी देशों में सर्दियों का मौसम काफी लंबे समय तक बना रहता है, यही कारण है कि इन्हें अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये गहन प्रसंस्करण उद्योग की ज़रूरत है।
- वर्षभर किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियाँ उत्पादित करते हैं। भारत की जलवायु विविधता के कारण मौसमी सब्जियों का उत्पादन उष्ण मैदानों से होते हुए ठंडे प्रदेशों तक पहुँच जाता है। यही कारण है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारी मात्रा में नविश करने के लिये सरकार पर किसी तरह की कोई अनविचार्य आर्थिक बाधयता नहीं है।

शीतशरुंखला, मूल्यवृद्धि तथा पररिक्षण अवसंरचना स्कीम

- इस स्कीम का उद्देश्य खेत से लेकर उपभोक्ता तक सतत एकीकृत शीतशरुंखला एवं पररिक्षण अवसंरचना सुवधियाँ उपलब्ध कराना है।
- इनमें उत्पादन स्थलों पर परी-शीतलन सुवधियाँ, रीफर वैन, चल शीतलन यूनिटें तथा बागवानी, जैविक उत्पाद, समुद्री उत्पाद, डेयरी, माँस और पॉल्ट्री के लिये प्रसंस्करण/बहु-पद्धति प्रसंस्करण/संग्रहण केंद्रों जैसी अवसंरचना सुवधियों से सृजित मूल्यवृद्धि केंद्र शामिल हैं।
- व्यक्त, उद्यमी समूह, सहकारी समितियाँ, स्व-सहायता समूह (एसएचजी), कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ), गैर-सरकारी संगठन, केंद्र/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो शीतशरुंखला समाधानों में व्यापारिक रुचिरखते हैं, स्कीम के अंतर्गत एकीकृत शीतशरुंखला एवं पररिक्षण अवसंरचना की स्थापना करने के पात्र हैं, साथ ही ये अनुदान राशिका भी लाभ उठा सकते हैं।
- आपको बता दें कि कोल्ड चेन में नविश को बढ़ावा देने की दृष्टि से वित्त मंत्रालय द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर श्रेणी के तहत कोल्ड चेन को कवर किया गया है।

बाधाएँ एवं समाधान

- उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अंतर्गत देश की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने, समावेशी विकास सुनिश्चित करने तथा अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभा पाने की पर्याप्त क्षमताएँ वदियमान हैं।
- इसके बावजूद ऐसे बहुत से बड़ि हैं जिनके संबंध में गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है, ताकि इस उद्योग की सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निवारण करते हुए देश की आर्थिक संवृद्धि में इसका सुदृढ़ स्थान सुनिश्चित किया जा सके।
- भारत में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या आवश्यक बुनियादी अवसंरचनाओं का अभाव है। भारत में न तो राष्ट्रीय राजमार्गों और न ही डेडकिंटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थिति इतनी अधिक सशक्त है कि देश के प्रत्येक हिस्से में मौजूद किसान को स्टोर मालिकों से संबद्ध किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त उत्पादन की तुलना में देश में शीत भंडारों एवं वेयर हाउसों की संख्या एवं क्षमता भी अपर्याप्त है।
- ध्यातव्य है कि वर्तमान में यह उद्योग विभिन्न राज्य स्तरीय एवं केंद्रीय कानूनों के माध्यम से शासित होता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। यदि इसके लिये किसी एक निति निकाय या प्राधिकरण की नियुक्ति की जाती है तो अधिक बेहतर तरीके से इस उद्योग का प्रबंधन किया जा सकता है।
- इसके अलावा न तो भारत में पश्चिमी देशों की भांति खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएँ मौजूद हैं और न ही यहाँ उपलब्ध जाँच मानकों में एकरूपता ही है। ऐसी स्थिति में निति रूप से वरिधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण न केवल उपभोक्ता बल्कि किसान के मन में भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है।
- साथ ही भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आवश्यक अनुसंधान एवं विकास की पर्याप्त कमी नज़र आती है, जिसके कारण इस उद्योग में न तो नवाचार ही हो पाता है और न ही जागरूकता का वातावरण तैयार हो पाता है।

नषिकर्ष

स्पष्ट रूप से यद्वि सभी बाधाओं का निवारण करते हुए आगे की राह प्रशस्त की जाती है तो पश्चिमी देशों की भाँति भारत में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को एक रोजगार उत्पन्न करने वाले, किसानों की आय में वृद्धि करने वाले, उपभोक्ताओं को ज़रूरत के उत्पाद समय पर उपलब्ध कराने वाले तथा देश की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में सूचीबद्ध किया जाने लगेगा। अत्यंत संभावनाशील उद्योग के रूप में यह क्षेत्र न केवल कृषि क्षेत्र के विकास में सहायक होगा बल्कि, पोषण की दृष्टि से भी लाभकारी साबित होगा।

प्रश्न: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु चलाई जा रही योजनाओं का परिचय देते हुए इनके मार्ग में आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये? किस प्रकार से यह देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक साबित हो सकती है संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिये?)

इस विषय में अतिरिक्त जानकारी के लिये पढ़ें :

⇒ [खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की पहल एवं उपलब्धियाँ](#)

- ⇒ [राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति](#)
- ⇒ [खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाई और कोल्ड चेन बुनियादी ढाँचा](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/will-food-processing-boost-prices-for-farmers>

